

## प्रेस विज्ञप्ति

### संसदीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

विकसित भारत @2047 की दिशा में : प्रभावी शासन एवं संसदीय प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु केंद्र-राज्य समन्वय पर चिंतन शिविर, ऊटी (तमिलनाडु)

भारत सरकार का संसदीय कार्य मंत्रालय 11-12 मई, 2026 को ऊटी, तमिलनाडु में विकसित भारत @2047 की दिशा में : प्रभावी शासन एवं संसदीय प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु केंद्र-राज्य समन्वय" विषय पर दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है।

यह चिंतन शिविर संसदीय एवं विधायी कार्यों के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु एक उच्च स्तरीय विचार-विमर्श मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री, मंत्रालय के राज्य मंत्रीगण, संसदीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसदीय कार्य मंत्री तथा विधायी कार्यों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

चिंतन शिविर के दौरान विचार-विमर्श का केंद्र विधायी कार्यप्रणाली, विधानमंडलों के डिजिटलीकरण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, लोकतांत्रिक सहभागिता तथा विधायी प्रभावशीलता से जुड़े विभिन्न विषय होंगे।

शिविर का एक प्रमुख ध्येय क्षेत्र राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन होगा, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को डिजिटल सदनों में परिवर्तित करना है। वर्तमान में 22 विधानमंडल नेवा मंच पर सक्रिय हैं, जबकि अन्य कई विधानमंडलों में इसका कार्यान्वयन उन्नत चरणों में है। नेवा से संबंधित चर्चाओं में सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में मंच के सार्वभौमिक अंगीकरण की रणनीतियों, सभी मॉड्यूलों के व्यापक उपयोग, अभिलेखीय एवं पुरालेखीय विधायी अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर विचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत बुद्धिमत्तापूर्ण खोज, बहुभाषीय अनुवाद, कार्यवाही का स्वचालित निर्माण, समकालिक व्याख्या तथा उन्नत विधायी विश्लेषण जैसी सुविधाओं पर भी चर्चा होगी।

चिंतन शिविर में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में समिति प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, जिसमें परामर्शदात्री समितियाँ तथा औपचारिक विधायी समिति तंत्र शामिल हैं, पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि कार्यपालिका की जवाबदेही को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा विधायी निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके।

युवा संसद कार्यक्रमों के संगठन एवं विस्तार का विषय भी चिंतन शिविर का एक महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। इसका उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।

चिंतन शिविर में विधायी प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों के प्रशिक्षण हेतु संस्थागत तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। चर्चा में नेवा सेवा केंद्रों को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित करने, मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा राज्यों के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने जैसे विषय शामिल होंगे।

राज्य विधानमंडलों की बैठकों की संख्या में वृद्धि के विषय पर भी व्यापक लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ बनाने तथा सहमति-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से विधायी प्रभावशीलता को बढ़ाने के संदर्भ में विचार-विमर्श किया जाएगा।

मंत्रालय को आशा है कि यह चिंतन शिविर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अनुभवों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के सार्थक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा तथा विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अनुरूप संसदीय एवं विधायी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एक समन्वित रूपरेखा विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा।

\*\*\*\*\*